

## धनी किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति का मुद्दा

प्रासंगिकता: जीएस-3: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे; प्रमुख फसलें- देश के विभिन्न भागों में फसल पद्धति, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली भण्डारण।

कीवर्ड्स: बिजली सब्सिडी नीति, सरकारी खजाने, भूजल, छोटे किसान, अर्ध-मध्यम किसान, कृषि गणना, नलकूप, पारिस्थितिक संतुलन।

प्रसंग:

- **मुफ्त बिजली का प्रावधान** 1997 से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह राज्य सरकार के वित्त पर बोझ डालता है और भूजल संसाधनों की कमी को बढ़ाता है।



मुख्य विचार:

- 2022-23 वित्तीय वर्ष में बिजली के लिए भुगतान अभूतपूर्व ₹7,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें लगभग ₹4,000 करोड़ उन बड़े किसानों को आवंटित किए गए हैं जिनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है।
  - नतीजतन, अब मुफ्त बिजली वितरण के नियमन पर विचार करने की आवश्यकता है।
- कई अध्ययनों ने संकेत दिया है कि बड़े किसानों के लिए मुफ्त बिजली की पहुंच को सीमित करने से राज्य के खजाने के लिए सालाना लगभग ₹2,500-3,000 करोड़ की बचत हो सकती है, जिसका उपयोग तब छोटे और सीमांत किसानों की बेहतरी के लिए किया जा सकता है।

वर्तमान स्थिति:

- 2015-16 की कृषि जनगणना से पता चला है कि पंजाब में लगभग 11 लाख सक्रिय भू-स्वामी किसान हैं जो लगभग 14.50 लाख नलकूपों का संचालन करते हैं।

- उनमें से, लगभग 1.6 लाख किसानों के पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है और उन्हें **सीमांत किसानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है**, जबकि 2.1 लाख के पास 2.5 से 5 एकड़ (**छोटे किसान**) और 3.7 लाख के पास 5 से 10 एकड़ (**अर्ध-मध्यम किसान**) हैं।
- इसके अतिरिक्त, लगभग 3.1 लाख किसानों के पास 10 से अधिक और 25 एकड़ तक भूमि है, और 60,000 किसानों के पास 25 एकड़ से अधिक भूमि है, जिन्हें **मध्यम और बड़े किसानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**
- **पंजाब के 11 लाख किसानों में से** 3.7 लाख किसान जिनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, उनके पास कई मोटर वाले नलकूप हैं और सीमांत और छोटे किसानों की तुलना में अधिक मुफ्त बिजली प्राप्त करते हैं।
- **मोंटेक सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा** 2020 में पंजाब सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार :-
  - राज्य द्वारा सालाना वहन की जाने वाली **कुल बिजली सब्सिडी का 56% मध्यम और बड़े किसानों को जाता है, जिनके पास 10 एकड़ से अधिक जमीन है।**
- **पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर** आयोग ने पहले 10 एकड़ से अधिक के मालिक या आयकर का भुगतान करने वाले किसानों को मुफ्त बिजली वापस लेने की सिफारिश की थी।
- इसलिए, सभी किसानों के लिए मूल्य निर्धारण मुक्त के रूप में एक निश्चित अश्वशक्ति तक केवल एक मोटर की अनुमति दी जानी चाहिए, इससे सब्सिडी कम होगी और पारिस्थितिक संतुलन बहाल होगा।

#### बिजली सब्सिडी :

- **चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल बिजली सब्सिडी बिल** लगभग ₹15,846 करोड़ होने की उम्मीद है, जिसमें कृषि उपभोक्ताओं के लिए ₹6,947 करोड़, घरेलू श्रेणियों (300 यूनिट मुफ्त सहित) के लिए ₹6,396 करोड़ और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ₹2,503 करोड़ करोड़।
- **1997-98 में**, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा सभी किसानों के लिए बिजली मुफ्त की गई थी, कुल बिजली सब्सिडी बिल केवल ₹604 करोड़ था। यह 1997-98 से 2022 तक बिजली सब्सिडी में **2,623.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि का अनुवाद करता है।**
- **पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड** (पीएसपीसीएल) के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में लगभग 14.5 लाख कृषि नलकूपों को मुफ्त बिजली मिलती है।
  - यह संख्या 1980 के दशक में 2.8 लाख नलकूपों से बढ़ गई है।
  - **नलकूपों में वृद्धि** से चावल की खेती में वृद्धि हुई है और चावल की खेती की जल-गहन प्रकृति के कारण जल तालिका में गिरावट आई है।
- **धान के रकबे का प्रतिशत** 1970-71 में 6 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 40 प्रतिशत हो गया है, जबकि **गेहूं के रकबे का प्रतिशत** 1970-71 में 40.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 44.9 प्रतिशत हो गया है- 22.
- इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान **दालों का रकबा** 7.3 से घटकर 0.4 प्रतिशत हो गया है, और तिलहन का रकबा 5.2 से घटकर 0.5 प्रतिशत हो गया है।

- बड़े किसानों द्वारा भूजल का दोहन सीमांत और छोटे किसानों के लिए उपलब्ध भूजल की मात्रा को कम करता है।

#### आगे की राह:

- एक मजबूत बिजली सब्सिडी नीति को लागू करना अनिवार्य है।
  - कृषि नलकूपों को विनियमित करने के उपाय शुरू कर दिए हैं , और पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (PSERC) को इसका पालन करना चाहिए और एक उपयुक्त कृषि बिजली सब्सिडी नीति स्थापित करनी चाहिए।
- राज्य पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए , यह बड़े किसानों के बहु-मोटर नलकूपों को एकल-चालित नलकूपों से बदल सकता है।
  - इसके अतिरिक्त , अधिकांश विद्युत नलकूपों को सब्सिडी वाले सौर नलकूपों से बदला जाना चाहिए

#### प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्र. कृषि विकास के लिए बिजली सब्सिडी प्रदान करने के संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हैं?

1. अधिक जल सघन कृषि उत्पादन की ओर फसल पैटर्न को बदलना।
2. इससे भूजल का अत्यधिक उपयोग हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जल तालिका में गिरावट आ सकती है।
3. इसने धान के मौसम के दौरान सबमर्सिबल पंपों की स्थापना और औद्योगिक गतिविधियों को कम करके किसानों की उत्पादन लागत को कम कर दिया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

- a) 1 और 2 केवल।
- b) 2 और 3 केवल।
- c) केवल 1 और 3।
- d) 1, 2 और 3.

उत्तर: (a)

#### स्पष्टीकरण-

##### बिजली सब्सिडी के प्रावधान के हानिकारक परिणाम

- विशेषज्ञों की राय है कि नलकूपों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति भूजल के अत्यधिक दोहन के लिए जिम्मेदार है। उनके अनुसार, बिजली सब्सिडी के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है, भूजल निकासी में वृद्धि हुई है, और चावल (धान) की खेती जैसे अधिक पानी गहन कृषि उत्पादन की ओर फसल पैटर्न को स्थानांतरित किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जैसे; भूजल का अत्यधिक दोहन भविष्य में कृषि उपयोग के लिए उपलब्ध भूजल की मात्रा को कम करता है। (इसलिए विकल्प 1 और 2 सही हैं)।

- धान की खेती को बढ़ावा देने के कारण किसानों को मुफ्त बिजली के प्रावधान का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जैसे कि धान की खेती को बढ़ावा देने के कारण जल संसाधनों की कमी, **सबमर्सिबल पंपों की स्थापना के माध्यम से किसानों के लिए उत्पादन लागत में वृद्धि** और धान के मौसम के दौरान औद्योगिक गतिविधियों में कमी आई है। (इसलिए विकल्प 3 गलत है)।

समाधान- चूंकि केवल पहला और दूसरा कथन सही हैं, सही विकल्प (a) है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्र. कृषि में बिजली सब्सिडी नीति को संबोधित करने और राज्य पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? चर्चा करें (150 शब्द)

स्रोत: बिजनेस लाइन